प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
21.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे
"आज के मुख्य समाचार"

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
- राज्य सरकार ने विधायकों की ऐच्छिक निधि को एक लाख रूपये बढ़ाने और करूणामूलक आधार पर नौकरी के लिए नीति लाने की घोषणा की।
- वित्त वर्ष 2025–26 के बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट।
- उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा–जरूरत व मांग के हिसाब से नए संस्थान खोलेगी सरकार।

अब समाचार विस्तार से.....

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के जाल में फसाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025–26 के आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि करूणामूलक आधार पर नौकरी के लिए एक महीने में सरकार नीति लाएगी। उन्होंने विधायकों की ऐच्छिक नीधि को एक लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड का सिविल विंग अन्य विभागों में मर्ज करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से 68 हजार करोड़ रुपए की उदार धनराशि प्राप्त हुई लेकिन भाजपा ने इसे प्रदेश का कर्ज लौटाने और कर्मचारियों की वेतन आयोग की देनदारियां चुकता करने की बजाय चुनावी रेवड़ियां बांटने पर खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में केवल 29 हज़ार 46 करोड़ रुपए का ऋण लिया।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के आगामी वित्त वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए हालांकि 3 हज़ार 9 सौ 76 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि आय के अतिरिक्त संसाधन जुटने पर यह राशि बढ़ाई जाएगी और साल के अंत तक प्रदेश में पूंजीगत खर्चों पर 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल में 40 हज़ार 3 सौ 52 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका एरियर नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी को कम करने और ऋण जुटाने की सीमा को सीमित करने के कारण प्रदेश को 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इसलिए बजट आकार में आगामी वित्त वर्ष के लिए ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच साल में आरडीजी और जीएसटी मुआवजे के रूप में 68 हजार करोड़ रुपए जबकि 11 हजार करोड़ रुपए कोरोना के कारण आई मंदी को देखते हुए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिले। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने प्रदेश सरकार की देनदारियों को चुकता नहीं किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया उनकी सरकार ने बीते दो सालों में सुशासन पर जोर दिया है और संसाधन जुटाने और फि फिजुलखर्ची को भी कम किया है।

वॉकआउट

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में जब बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कर्ज उठाने को लेकर दिए गए आंकड़ों का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान अपनी सीट पर खड़े हो गए और अपना पक्ष रखने की बात करने लगे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर पूरा विपक्ष ही अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और कुछ देर के हंगामे व नारेबाजी के बाद सदन से उठकर बाहर चला गया। वॉकआउट के बाद जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हर समय झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए कर्ज़ पर 38 हज़ार 2 सौ 76 करोड़ रूपये का ब्याज और ऋण की अदायगी के रूप में चुकाया है, बावजूद इसके प्रदेश का विकास नहीं रूकने दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केन्द्र और पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

प्रश्नकाल

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जरूरत और मांग की हिसाब से नए संस्थान खोलेगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान संस्थान खोलने व बंद करने संबंधी सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी सदस्य पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए बंद संस्थानों के बजट दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसे संस्थानों को सरकार फिर से खोलने पर विचार करेगी। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व जयराम सरकार ने सत्ता में वापिस आने के लिए आखिरी 6 महीने में एक हज़ार ऐसे संस्थान खोले जिनके लिए न बजट और न ही पद सृजित किए थे। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का एक–एक डिवीजन खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र और ग्रामीण विकास में सरकार संस्थानों का युक्तिकरण कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के हित में जहां भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी वहां खोलेंगे लेकिन अंधे तरीके से संपदा को नहीं लुटाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूर्व सरकार के खोले गए संस्थान बंद रखे जाएंगे उनको सरकार खोल रही है मगर मेरिट व डी–मेरिट के आधार पर इनको खोला जा रहा है। इसी मुद्दे पर विधायक राकेश जमवाल, सतपाल सत्ती और डॉक्टर हंसराज ने भी अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित प्रतिपूरक सवाल पूछे। विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में एफआरए के तहत 3 हजार 3 सौ 27 मामले मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एफआर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अप्रैल महीने में पंचायती राज प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हित्त में इस कानून को लागू करेगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारों ने हमेशा ही इस कानून को ठंडे बस्ते में डाले रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी संबंध में विधायक अनुराधा राणा के प्रतिपूरक सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि एफआरए के तहत 52 मामले स्वीकृत किए गए हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यदि एसआईडीसी में काम करने में किसी ठेकेदार की कोताही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

चर्चा

राज्य के वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट पर विधानसभा में आज अंतिम दिन भी चर्चा जारी रही। इस दौरान सत्तापक्ष ने जहां बजट को सराहा वहीं विपक्ष ने इस बजट को सिरे से पूरी तरह से नकारा। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को उद्योग पैकेज दिया जिससे यहां निवेश बढा। इसके बाद मोदी सरकार ने हिमाचल को कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं जिसका पूरा श्रेय केन्द्र सरकार को जाता है। सतपाल सिंह सत्ती ने हिमकेयर योजना को चलाए रखने की मांग की। उन्होंने कानून व्यवस्था की खस्ता स्थिति का भी उल्लेख किया। सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना के पेखूवेला और गुजरात में लगाए गए सोलर प्लांट में 100 करोड रूपए का फर्क है जिसकी खोजबीन होनी चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए विधायक विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर दिखाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट से ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ करने और विधायकों को ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 25 लाख करने की मांग की। चर्चा में विधायक अनिल शर्मा ने भी हिस्सा लिया।

विमल नेगी

हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में भाजपा ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को निष्पक्ष जांच संबंधी एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित विधायक दल ने इस मामले की सीबीआई जांच और एचपीपीसीएल की दो वर्ष की गतिविधियों की निष्पक्ष जॉच की मांग भी राज्यपाल के समक्ष रखी है ताकि विमल नेगी के परिजन संतुष्ट हो सकें।

" मुख्य समाचार एक बार फिर"

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
- राज्य सरकार ने विधायकों की ऐच्छिक निधि को एक लाख रूपये बढ़ाने और करूणामूलक आधार पर नौकरी के लिए नीति लाने की घोषणा की।
- वित्त वर्ष 2025–26 के बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट।
- उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा–जरूरत व मांग के हिसाब से नए संस्थान खोलेगी सरकार।